विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधित कार्यसूची वीरवार, 17 दिसम्बर, 2020 / 26 अग्रहायण, 1942 (शक्) 02.00 बजे अपराहन2.00 बजे अपराहन

राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमित से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगेः

1. श्री सोम दत्त

6. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी

2. श्री मोहन सिंह बिष्ट

7. श्री अजय महावर

3. श्री जय भगवान

8. श्री जितेन्द्र महाजन

4. श्री नरेश बाल्यान

9. श्री अभय वर्मा

5. श्री भूपेन्द्र सिंह जून

सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात : 2.

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगेः

- 1. दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड का वित्त वर्ष 2017-18 हेत् वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
- 2. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड का वित्त वर्ष 2018-19 हेतु 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी
- 3. इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वित्त वर्ष 2018–19 हेत् 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

सरकारी संकल्प (नियम–90) : 3.

श्री कैलाश गहलोत, माननीय राजस्व मंत्री कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के संबंध में सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :

श्री सौरभ भारद्वाज

श्री रोहित कुमार

श्री कुलदीप कुमार

"दिल्ली के नगर निगमों में वित्तीय कुप्रबंधन और 2500 करोड़ रूपये के कथित घोटाले" के संबंध में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

दिल्ली 17 दिसम्बर, 2020 सी. वेलमुरूगन सचिव

कृषि कानूनों पर सरकारी संकल्प (नियम-90) की विषय वस्तु

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत की संसद ने हाल ही में निम्नलिखित तीन काूननों को अधिनियमित किया है, जिन्हें आमतौर पर 'कृषि कानूनों' के रूप में उल्लिखित किया जा रहा है और जो पूरे देश में विद्यमान कृषि प्रथाओं में व्यापक परिवर्तन करते हैं:

- (क) कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (संर्वद्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020,
- (ख) कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण), मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवाएँ अधिनियम, 2020, और
- (ग) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020,

आगे, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों से, देश भर के किसान आंदोलित हैं, जो न केवल किसानों के हितों के विरुद्ध हैं बल्कि आम आदमी के लिए भी हानिकारक हैं;

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह विश्वास व्यापक हो चुका है कि इन कृषि कानूनों को वर्तमान सत्तासीन सरकार द्वारा कुछ कॉरपोरेट्स के इशारे पर संसद में लाया गया है, जो अंततः किसानों की आय को नुकसान पहुँचा सकते हैं;

और, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में किसान भीषण सर्दियों में दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से कुछ की जान भी चली गई है;

इस विचार के साथ कि जिस प्रकार हितधारकों से बिना किसी विचार—विमर्श के और राज्यसभा में उचित मतदान न होने पर भी, जिस प्रकार संसद में इन बिलों को लाया गया और भारत सरकार ने किसानों की उचित मांगों पर सहमत होने से भी इनकार कर दिया है, इससे कृषक समुदाय में अत्यंत आक्रोश है;

और दिल्ली सरकार किसानों की मांग का खुले दिल से समर्थन करने के लिए संकल्पबद्ध है ;

यह सदन तीनों अधिनियमों को अस्वीकार करता है और भारत सरकार से ईमानदारी से अपील करता है कि राष्ट्र के हित में, संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की गारंटी देने के लिए अलग से बिल पारित किया जाए और अन्य सभी माँगें स्वीकार की जाए।"

कैलाश गहलोत मंत्री (राजस्व)

<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

REVISED LIST OF BUSINESS

Thursday, 17 December 2020 / 26 Agrahayan 1942 (*Saka*) 02.00 PM

NATIONAL SONG-VANDE MATARAM

1. Special Mention (Rule-280):

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

- 1. Sh. Som Dutt
- 2. Sh. Mohan Singh Bisht
- 3. Sh. Jai Bhagwan
- 4. Sh. Naresh Balyan
- 5. Sh. Bhupinder Singh Joon
- 6. Sh. Akhilesh Pati Tripathi
- 7. Sh. Ajay Mahawar
- 8. Sh. Jitender Mahajan
- 9. Sh. Abhay Verma

2. Papers to be laid on the Table:

Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Power to lay copies of the following on the Table of the House:

- i. Annual Report of the Delhi Power Company Limited (DPCL) for the financial year 2017-18 (Hindi & English Version).
- ii. Annual Report of Delhi Transco Limited (DTL) for the financial year 2018-19 (Hindi & English Version).
- iii. Annual Accounts of Indraprastha Power Generation Co. Limited (IPGCL) & Pragati Power Corporation Limited (PPCL) for the financial year 2018-19 (Hindi & English Version).

3. Government Resolution (Rule-90):

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Revenue to move a Government Resolution on Farm Laws and Farmers agitation (Text of Resolution attached).

4. Short Duration Discussion (Rule-55):

Shri Saurabh Bharadwaj

Shri Rohit Kumar

Shri Kuldeep Kumar

To initiate discussion on issues related to 'Financial mismanagement in the Municipal Corporations of Delhi and alleged scam of Rs.2500 Crores'.

Delhi 17th December 2020 C. Velmurugan Secretary

Text of Government Resolution (Rule-90) on Farm Laws:

"Taking note of the fact that the Parliament of India has recently enacted following three Laws, commonly referred as 'Farm Laws', which make wide ranging changes in the existing farm practices throughout the country

- (a) The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020;
- (b) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and
- (c) The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020;

Taking further note of the fact that farmers across the country have been agitated with various provisions of these laws, which are considered to be detrimental not only to the interests of the farmers but also the common man;

Taking note of the fact that there is wide spread belief that these Farm Laws have been pushed through the Parliament by the present Government in power at the behest of certain corporates which may ultimately lead to loss of income for the farmers;

Taking further note of the fact that large number of farmers have been protesting on the borders of Delhi in chilly winters and some of them are also reported to have lost their lives;

With the considered view that the farmer community has been extremely agitated at the way these Bills have been pushed through in the Parliament without any consultation with the stakeholders, without proper voting in Rajya Sabha and the refusal of the Government of India to agree to the rightful demands of the farmers;

And the resolve of the Government of NCT of Delhi to wholeheartedly support the demand of the farmers;

This House rejects all the three enactments and earnestly appeals to the Government of India that in the interest of the nation, the Farm Laws passed by the Parliament may be repealed with immediate effect and separate Bill guaranteeing government purchase of all crops at MSP be passed by the Parliament and all other demands be accepted.

KAILASH GAHLOT MINISTER (REVENUE)